वसूलियों पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेशों में न्यायालयों ने कोई कारण नहीं बताये थे। तथापि वसूली को रोकने के लिए पार्टियों द्वारा दिये गये आवेदन-पत्रों में तर्क किया गया था कि चीनी की मिलों द्वारा उत्पादित तथा उपयोग की गयी कार्बन डाई-आक्साइड पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने में, अन्य बातों के साथ साथ, विधि के मारगर्भित प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं तथा मांगों की वसूली कष्ट के रूप में कार्य करेगी। मुख्य याचिकाओं पर निर्णयपर्यन्त न्यायालयों द्वारा स्टे आर्डर जारी किये गये थे। चीनी पर भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी दो मामलों के बारे में, ऐसी ही परिस्थितियों के अधीन, स्टे आर्डर जारी किये गये हैं। शेष २२ मामलों में भी पार्टियों ने सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष मांगों को चुनौती दी है।

(ख) कार्बन डाई-आक्साइड पर उत्पादन शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अधिकतर मामलों पर उच्च न्यायालयों ने सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिये हैं, लेकिन प्रभावित चीनी मिलों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की छुट्टी की मंजूरी दे दी गयी है। चीनी मिलों को उच्च न्यायालय द्वारा दो महिने की अवधि के लिए अन्तरिम रोक भी मंजूर कर दी गयी है। शेष मामले अभी न्यायालयों अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR SAHU): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) It was stated in the reply to the Rajya Sabha Unstarred Question No. 562 on the 23rd September, 1964 that the affected Sugar Mills have disputed the demands for duty either in the Courts of Law and obtained stay orders or have filed appeals, etc., before the concerned Central Excise appellate authorities.

The annexure to that reply contained particulars in respect of 52 sugar mills. Not all of them are court cases. The courts have issued stay orders in 30 cases only, out of which 28 relate to recovery of duty on carbon dioxide and 2 cases relate to excise duty demands on sugar. The courts did not assign any reasons in the orders staying the recoveries. However, applications moved by the parties for the stay of recovery contended that the levy of an excise duty on carbon dioxide produced and utilized by the sugar mills, *inter alia*, involved substantial questions of law and the recovery of demands would work as a hardship. Pending decision on the main petitions, stay orders were issued by the courts. In regard to the two cases relating to excise duty on sugar also, stay orders have been issued under similar circumstances. In the remaining 22 cases the demands are challenged by the parties before the concerned Central Excise appellate authorities.

(b) Most of the cases relating to recovery of excise duty on carbon dioxide have since been decided by the High Courts in favour of the Government, but the affected sugar mills have been granted leave to appeal to the Supreme Court. Interim stay for a period of two months has also been granted by the High Court to the sugar mills. The remaining cases are still pending before the Courts or Central Excise appellate authorities.]

जबलपुर नगर का श्रेणीकरण

*४८२. **पंडित भवानी प्रसाद तिवारी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६३ के महीने में कौंसिल आफ ट्रेड यूनियन्स, जबलपुर

†[ ] English translation.

ने, जो लगभग ५०,००० केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार को एक ज्ञापन पत्र भेजा था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि जबलपुर नगर को 'बी' श्रेणी का नगर इस आधार पर घोषित किया जाये कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लाभ एवं प्रोत्साहन मिलने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

†[CLASSIFICATION OF JABALPUR CITY

*482. PT. BHAWANIPRASAD TIWARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state·

(a) whether a memorandum was submitted to Government by the Council of Trade Unions, Jabalpur representing about 500,000 Central Government employees working at Jabalpur, during the month of December, 1963 requesting that Jabalpur city be declared as a 'B' class city on the ground that benefits and incentives should be given to Central Government employees; and

(b) if so, what action has been taken by Government thereon?]

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) जी नहीं । जान पड़ता है वित्त मंत्रालय को इस संस्था का ऐसा कोई ज्ञापन नही मिला ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR SAHU): (a) No, Sir. No such memorandum appears to have been received in the Finance Ministry from this body.

(b) Does not arise.]

†[ ] English translation.

SEMINAR ON EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

*483. SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the recommendations made by the seminar on employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes held in Delhi have been received by Government; and

(b) if so, what are the recommendations and whether any of them have been accepted by Government?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B. R. BHAGAT): (a) Yes.

(b) A printed report is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—3754/64.] The recommendations are under the consideration of the Central Ministries and the State Governments.

कस्टम प्राधिकारियों की तस्करों के बीच साठगांठ

*४८४. **श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' :**
श्री महाबीर प्रसाद भार्गव :
श्री राम सहाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० नवम्बर, १९६४ को मद्रास में कस्टम के कलैक्टरों के सम्मेलन में उन्होंने यह कहा था कि कस्टम विभाग के कर्मचारी और तस्कर व्यापारियों के बीच साठगांठ है और सोने को चोरी छिपे लाने के लिए बम्बई और कलकत्ता 'काला धब्बा' हैं; और यह भी कि कस्टम विभाग के कर्मचारियों की तस्करों के साथ साठगांठ से विभाग की अप्रतिष्ठा हुई है; और